

Annexure B

**Notifications issued in pursuance
of
IT & ITES Policy 2007**

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

CIRCULAR

The requirement of Internet Connectivity has increased in Government departments across the State as many Government departments have central web-based applications or Internet website that needs to be accessed, by their district and field level offices.

In light of the above fact, State Government has decided that BSNL's Broadband Connection Facility may be availed by the departments in all government offices where no alternate connectivity exists.

This is subject to the following conditions:

1. One Broadband internet connection per office may be taken. Initially the 256 KBPS Bandwidth Plan of BSNL of minimum tariff (presently Rs. 700/- per month) can be taken. BSNL has waived off Installation Charges and Security Deposit (letter enclosed)
2. For higher bandwidth plan, justification for the same may be got vetted from DoIT&C,
3. No additional budget provisions will be made available for the Broadband connectivity. The expenditure on the usage of Broadband Internet Service should be met by the Departments from the budget available for 'Office Expense (OE)'.
4. When the connectivity in the Department / Office is made available under SecLAN / RSWAN project, the BSNL Internet Broadband Connectivity would have to be terminated. It would be the personal responsibility of the concerned Head of the Department and official in the Administrative Department to ensure the same.
5. The facility may be availed by the field offices only after specific approval of the concerned Head of the Department.

This bears the approval of Finance Department, Government of Rajasthan vide ID. no. 2161 dated 08.12.2006.

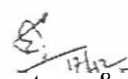

(CK. Mathew)
Principal Secretary

No. F 5(282) / DoIT/ Tech/06/2269

Jaipur, Dated: 18/12/06

Copy for information and necessary action to:

1. Accountant General, Rajasthan.
2. Chief Secretary, Government of Rajasthan.
3. All Additional Chief Secretaries, Government of Rajasthan.
4. All Principal Secretaries / Secretaries / Head of the Departments, Government of Rajasthan.
5. All District Collectors/ Superintendents of Police, Government of Rajasthan.
6. Director (Budget), Finance Department, Government of Rajasthan.
7. DGM (IT & BD), Office of CGMT, BSNL, Jaipur for issuing directions to all concerned in this regard.


Deputy Secretary & Director

O/o Chief General Manager
Rajasthan Telecom Circle
Sardar Patel Marg, Jaipur-302008
Fax no. 0141-2375838

 भारत संचार निगम लिमिटेड
BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

No. BD/04-25/DoIT&C/2006-07/

Dated: 16-12-2006

To,
The Director (IT)
DoIT&C,
Govt. of Rajasthan.

**Subject: Offer for the special tariff package for Broad Band Connection -
Regarding.**

Ref.- letter No. F5(282)DOIT/Tech/06/2210 Jaipur, Dated 11.12.2006.

Dear Sir.

With reference to above cited subject and letter under reference. I am thankful for your trust in BSNL for providing broadband connection to various offices of Govt. of Rajasthan. We offer following tariff as per your requirement.

1. The tariff packages for Broadband service are enclosed herewith.
2. As a special case following discounts are offered to Govt. of


Rajasthan:

Installation charge : **Waived off**

Security deposit : **Waived off**

For any further clarification please feel free to contact me.

Assuring always the best telecom solutions/services at the lowest price.


DGM(IT&BD)
O/o CGMT, Jaipur
Ph. 2366639

(A) DATAONE- BUSINESS PLANS

Particulars	Tariff in Rs.				
	Business NEW 700	Business 1200	Business 3000	Business 5000	Business 9000
Bandwidth	256 Kbps	256 Kbps	512Kbps	1 Mbps	2 Mbps
Single/ Multl User-(SU/MU)	SU	SU	MU	MU	MU
Monthly Charges (Rs)	700	1200	3000	5000	9000
Discounted Annual Payment Option to Customers (Rs)	7000	12000	30000	50000	90000
Download/ Upload Limit (GB) per month	2 GB	4 GB	10 GB	20 GB	40 GB
Additional Usage Charges/MB beyond free download/upload limit (Rs)	1.20	1.00	0.80	0.60	0.60
Free E-mail IDs/Space (Per E-mail ID)	1/5MB	1/ 5 MB	2 / 5 MB	2 / 5 MB	4 / 5 MB
Static IP Address (On Request)	Not Available	Not Available	Not .Available	One	One
Web Hosting Space (On	Not Available	Not Available	Not Available	5 MB	5 MB
Domain Name (On Request)	Not Available	Not Available	Not Available	One	One
Security Deposit	1 month rental: waived off	1 month rental: waived off	1 month rental: waived off	1 month rental: waived off	Rs. 5000: waived off
Minimum Hire Period	One Month	One Month	One Month	One Month	One Month

(B) Modem on Outright purchase:

Ports	Modem Type			
	Type-I	Type-II	Type-III	Type-IV
Ethernet	One	One	Four	Four
Wi-Fi	-	One-	One	
USB	One	-	-	-
Charges (Rs.)	1200	1800	1200	1800

(C) Modem on Rent:

Particulars	Modem Type			
	Type-1	Type-II	Type-III	Type-IV
Monthly rental	Rs. 60* p.m.	Rs. 90* p.m.	Rs. 60* p.m.	Rs. 90* p.m.

* New Rental with effect from 01-12-2006.

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप - 3)

क्रमांक प.6(48)/प्र.सु./अनु.3/2004/
2007

जयपुर, दिनांक 15.02.

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2004 द्वारा गठित सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल (I.T. TASK FORCE) का नाम इस आदेश द्वारा राज्य ई-प्रशासन परिषद (State e-Governance Council) किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान की जाती है। इस आदेश द्वारा महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी) को पूर्व में नामित सदस्यों के अतिरिक्त ई-प्रशासन परिषद में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

अतः राज्य ई-प्रशासन परिषद (State e-Governance Council) का निम्नानुसार गठन एतद् द्वारा किया जाता है:-

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	संयोजक
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त (अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सरकारी सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग (अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सरकारी सदस्य
6.	श्री एन.आर. नारायण मूर्ति, अध्यक्ष, इन्फोसिस (अथवा नामित प्रतिनिधि)	गैर सरकारी सदस्य
7.	श्री किरण कार्णिक, अध्यक्ष, नास्कॉम	गैर सरकारी सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र पंवार, अध्यक्ष, एन.आई. आई.टी लिमिटेड	गैर सरकारी सदस्य
9.	श्री आर.चन्द्रशेखर, आई.ए.एस., अतिरिक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
10.	डा. अशोक झुनझुनवाला, प्रोफेसर, आई.आई.टी. चेन्नई	गैर सरकारी सदस्य
11.	महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी)	सदस्य

पूर्व में जारी आदेश में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त ई-प्रशासन परिषद निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित करेगी:-

1. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र का निर्धारण
2. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य योजना का पुनरीक्षण
3. सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्राथमिकता एवं नीति निर्धारण
4. ई-प्रशासन में नागरिक केन्द्रित परियोजनाओं को प्रोत्साहन

ई-प्रशासन परिषद का प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), नई दिल्ली
9. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
11. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान
12. ई-प्रशासन परिषद के समस्त सदस्य (परिषद के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
13. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
14. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय- I, II, III एवं IV)
15. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
16. निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप- 3)

क्रमांक प.6(57)/प्र.सु./अनु.3/2004(1)/

जयपुर, दिनांक 15.02.

2007

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2004 द्वारा गठित सर्वाधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) का नाम इस आदेश द्वारा राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee) किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान की जाती है। इस आदेश द्वारा महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी) को पूर्व में नामित सदस्यों के अतिरिक्त राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

अतः राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee) का निम्नानुसार गठन एतद् द्वारा किया जाता है:-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त	सदस्य
4.	शासन सचिव, योजना	सदस्य
5.	संबंधित विभागों के सचिव	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित प्रमुख तकनीकी संस्थानों, तकनीकी के दो विशेषज्ञ (जैसे IIT, BITS, Pilani, LNMIT etc.)	विशेष आमंत्रित
7.	महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी)	सदस्य
8.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य सचिव

पूर्व में जारी आदेश में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee) निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित करेगी:-

1. मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का मूल्यांकन
2. सूचना प्रौद्योगिकी नीति का क्रियान्वयन एवं पुर्नरीक्षण
3. केन्द्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना

4. विभाग स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का पुर्नरीक्षण
5. नागरिक केन्द्रित परियोजनाओं का प्रारूप निर्धारण
6. सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचे का विस्तार एवं विकास
7. सूचना प्रौद्योगिकी की लाभदायक परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण

राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति का प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,



उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. महानिदेशक, नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), नई दिल्ली
9. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
11. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान
12. राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति के समस्त सदस्य (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
13. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
14. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय- I, II, III एवं IV)
15. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है।
16. रक्षित पत्रावली



उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप-3)

क्रमांक प.6(57)/प्र.सु./अनु.3/2004(3)/
2007

जयपुर, दिनांक 15.02.

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2004 द्वारा गठित परियोजना अनुमोदन समिति (Project Approval Committee) का नाम इस आदेश द्वारा राज्य ई-प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान की जाती है। इस आदेश द्वारा राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी) को पूर्व में नामित सदस्यों के अतिरिक्त राज्य ई-प्रशासन लक्ष्य दल में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

अतः राज्य ई-प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) का निम्नानुसार गठन एतद् द्वारा किया जाता है:-

1.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, (वित्त) अथवा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
3.	संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव / सचिव	सदस्य
4.	शासन सचिव, योजना	सदस्य
5.	संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनीत प्रमुख तकनीकी संस्थानों, तकनीकी के दो विशेषज्ञ (जैसे IIT, BITS, Pilani, LNMIT etc.)	विशेष आमंत्रित
7.	राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी)	सदस्य
8.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य सचिव

पूर्व में जारी आदेश में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त राज्य ई-प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित करेगी:-

मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को अनुमति देना

1. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को बनाने में विभिन्न विभागों को सहायता उपलब्ध कराना
2. शीर्षस्थ समिति के लिए तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करना
3. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए सामर्थ्य विकसित योजनाओं का क्रियान्वयन
4. प्रापण एवं अनुबन्ध प्रबन्धन
5. वित्तीय प्रबन्धन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना

राज्य ई-प्रशासन लक्ष्य दल का प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान
11. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय- I, II, III एवं IV)
13. राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), राजस्थान, जयपुर
14. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है।
15. रक्षित पत्रावली

उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप- 3)

क्रमांक प.6(57)/प्र.सु./अनु.3/2004(2)/
2007

जयपुर, दिनांक 15.02.

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2004 द्वारा गठित तकनीकी समिति (Technical Committee) का नाम इस आदेश द्वारा परियोजना ई-प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान की जाती है। इस आदेश द्वारा राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी) को पूर्व में नामित सदस्यों के अतिरिक्त परियोजना ई-प्रशासन लक्ष्य दल में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

अतः परियोजना ई-प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) का निम्नानुसार गठन एतद् द्वारा किया जाता है:-

1.	संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव / सचिव	सदस्य
2.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य सचिव
3.	संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	मुख्य लेखाधिकारी / संबंधित विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी	सदस्य
5.	विभाग में पद स्थापित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर / प्रोग्रामर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संबंधित अन्य अधिकारी	सदस्य
6.	यदि आवश्यक हो तो निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित अधिकतम दो तकनीकी विशेषज्ञ	विशेष आमंत्रित
7.	राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी)	सदस्य
8.	सिस्टम एनालिस्ट-प्रथम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य सचिव

पूर्व में जारी आदेश में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त परियोजना ई-प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित करेगी:-

1. कार्य योजना एवं निपुणता निर्धारण को अन्तिम रूप देना
2. परियोजना प्रबन्धन एवं कार्य निर्धारण
3. आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता, संविदा पर लेने की प्रक्रिया एवं संसाधनों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण

परियोजना ई-प्रशासन लक्ष्य दल का प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,




उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
11. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय- I, II, III एवं IV)
13. राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), राजस्थान, जयपुर
14. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है।
15. रक्षित पत्रावली



उपशासन सचिव

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
वैशाख 3, सोमवार, शाके 1929-अप्रैल 23, 2007 <i>Vaisakha 3, Monday, Saka 1929-April 23, 2007</i>		

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)
सामान्य कानूनी नियम।

**DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY &
COMMUNICATIONS**

NOTIFICATION

Jaipur, April 18, 2007

G.S.R. 6.-In exercise of the powers conferred by section 90 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000), the State Government hereby makes the following rules; namely :-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Rajasthan Cyber Cafe Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000);

(b) "Log Register" means the Register maintained by the Cyber Cafe Owner/Network Service Provider for using the Cyber Cafe or Network Services;

(c) "User" Means a person who uses the Computer in a Cyber Cafe;

(d) "Cyber Cafe" means premises where the Cyber Cafe Owner/Network Service Provider provides the computer services including Internet access to the public in any of its forms, either on payment or free of charge for any purpose including recreation or amusement; and

(e) "Police Authority" mean the Police officers not below the rank of Deputy Superintendent of Police.

3. Responsibilities of the Cyber Cafe Owners.- (1) The owner of the Cyber cafe shall take sufficient precaution so that computers and computer systems in the Cyber Cafe are not used for any illegal or criminal activity.

(2) Cyber Cafe Owner/Network Service Provider shall not allow any User to use his Computer, Computer System and/or Computer Network without the identity of the User being established before him. The intending user may establish his identity by producing any Photo Identity Card Issued by any school or College or a Photo Credit Card of any bank or Passport or Voters Identity

Card or PAN Card issued by Income-Tax authorities or Photo Identity Card issued by the Employer or Driving License to the satisfaction of Cyber Cafe Owner.

(3) After the identity of the User is established, the owner of the Cyber Cafe or the manager or the attendant or on his behalf any authorized person managing the Cyber Cafe shall obtain and maintain the following information in the Log Register for each user:

- (i) Name of the User
- (ii) Age and Sex of the User
- (iii) Proof of Identity Produced and its details/Number
- (iv) Present residential address of the User
- (v) IP address of the computer used
- (vi) Name of Network service provider
- (vii) Log in time
- (viii) Log out time
- (ix) Photograph of the user taken by Cyber Cafe Owner through Web Cam
- (x) Signature of User.

(4) The Cyber Cafe Owner/Network Service Provider will keep on record the photo copy of the proof of identity.

(5) All the computers in the Cyber cafe shall be equipped with the safety software so as to avoid access to the web sites relating to pornography, obscenity, terrorism and other objectionable materials.

(6) All time clocks in Cyber Cafes must be regularly checked and synchronized with Indian Standard Time (IST).

(7) Maintaining proper account of the User as explained shall be the responsibility of the Cyber Cafe Owner/Network Service Provider.

(8) Log Register and the Photograph of the User shall be maintained by the Cyber Cafe Owner/Network Service Provider for a minimum period of One Year and shall be provided to Law enforcement agencies as and when required.

(9) The Cyber Cafe owner shall be responsible for storing and maintaining backup of following logs for at least six months:

(A) Proxy logs

(B) Any other logs created by network software, if any.

(10) If any activity of the Visitor/user is of suspicious nature, the owner of the Cyber Cafe shall immediately inform the nearest Police Station.

4. Inspection of Cyber Cafes - (1) Police authorities may inspect Cyber Cafes at all reasonable time to ensure compliance of these rules.

(2) If any Cyber Cafe Owner/Network Service Provider fail to maintain the Log register and records, he shall be liable for penalties as provided in the Act or any other Law, for the time being in force.


[No. F.5 (92)DoIT/Tech/99/Part-II/ML-178]

By Order of the Governor,
दिनेश कुमार,

Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur

973
3-4-07

	राजस्थान राज-पत्र	R.N.I. No.-RAJ BIL/2000/1717 POSTAL REGD. No. J.P.C./3544/02/23-05 RAJASTHAN GAZETTE
	विशेषांक	"Extraordinary"
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 18, शुक्रवार, भाके 1928—मार्च 9, 2007 Phalgun 18, Friday, Saka 1928—March 9, 2007		

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (11)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं ।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 7, 2007

एस. ओ. 413:- यतः राज्य सरकार के अभिमत में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की प्रथम अनुसूची में "सूचना, दूरसंचार तकनीक से संबंधित" इकाइयों को जनहित में जोड़ा जाना समीचीन एवं आवश्यक है।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम-14) की धारा-40 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिनियम की अनुसूची में विद्यमान मद सं. -33 के पश्चात निम्नलिखित मद में जोडती है:-

34- " सूचना एवं संचार तकनीक से संबंधित" समस्त इकाइयां।

[संख्या एफ13(8) श्रम/वि./95-11/3635]

राज्यपाल के आदेश से,
बजरंग लाल,
अति. श्रम आयुक्त एवं,
पदेन उप शासन सचिव।

479

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

Government of Rajasthan
Urban Development & Housing Department

No.F.10(53)UDD/3/06

Jaipur, Dated: 14.11.07

NOTIFICATION

The State Government being of the opinion that it is necessary in the public interest to boost up the Information Technology Industries and IT enabled services in the State, hereby provides the Private Information Technology Units or Parks, existing or established upto 31st March 2012, shall be assisted in getting the Change in Land Use made in the Master Plan / Zonal Development Plan or under any law, rule or regulation, in the use zones mentioned below wherever feasible for location of such units or parks on the following terms and conditions, namely:-

1. Use zone:
 - a. Residential use
Provided the units seeking change in land use are:
 - (i). located on minimum 60ft wide ROW road and
 - (ii). Non-polluting and do not create traffic problems.
 - b. Institutional use (on same terms and conditions as in (a) above)
 - c. Commercial use
 - d. Industrial use

The above shall be applicable to the Information Technology Units (IT Units), as specified in the annexure appended to this notification or Information Technology Parks (IT Parks).

2. Information Technology Units (IT Units) or Information Technology Parks (IT Parks) shall be duly certified as such by the Director, Department of Information Technology & Communication, for availing the benefits under this notification.

By Order of the
Governor,



(Sunil Kumar Sharma)
Dy. Secretary to
Government

ANNEXURE

CATEGORIES OF INDUSTRIES INCLUDED IN THE SCOPE OF INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY / UNITS

A. Computing devices including :-

Desktop
Personal Computer
Servers
Work-station
Nods
Terminals
Network PC
Home PC
Laptop Computers
Note book Computers
Palm top Computers/PDA

B. Network controller cards/Memories including :-

Network interface card (NIC)
Adaptor-ethernet / PCI / EISA / combo / PCMCIA
SIMMs-Memory
DIMMs-Memory
Central Processing Unit (CPU)
Controller-SCSI / Array
Processors-Processor / Processor Power Module / Upgrade

C. Storage Units including :-

Hard Disk Drives / Hard Drives
RAID Devices & their Controllers
Floppy Disk Drives
C.D. ROM Drives
Tape Drives – DLT Drives / DAT
Optical Disk Drives
Other Digital Storage Devices

D. Printers & Output Devices including :-

Dot-matrix
Laser jet

6

Ink jet
Desk jet
LED printers
Line printers
Plotters
Pass book Printers

E. Net working Products including: -

Hubs
Routers
Switches
Concentrators
Trans-receivers

F. Software including: -

Application Software
Operating System
Middle Ware / Firm Ware

G. Power Supplies to Computer Systems including: -

Switch Mode Power Supplies
Uninterrupted Power Supplies

H. Net working / Cabling & related Accessories : -

(related to I.T. Industry)
Fibre Cable
Copper Cable
Cables
Connectors, Terminal Blocks
Jack Panels, Patch Cord
Mounting Cord, Patch Panels
Back Boards, Wiring Blocks
Surface Mount Boxes

I. Electronic Components: -

Printed circuit Board Assembly / populated PCB
Printed Circuit Board / PCB
Transistors
Integrated Circuits / Ics
Diodes / Thyristor / LED

6

Registers
Capacitors
Switches (On / Off, Push- button, Rocker etc.)
Plugs / Sockets / Relays
Magnetic Heads, Print Heads
Connectors
Microphones / Speakers
Fuses

J. Tele-communication Equipment including: -

Telephones
Videophones
Facsimile Machines / Fax cards
Tele-Printers / Telex machines
PABX / EPABX / RAX /MAX –Telephone exchange
Multi plexers / Muxes
Modems
Telephone Answering Machines
Tele-Communication Switching Apparatus
Antenna & Mast
Wireless Datacom Equipment
Receiving Equipments like pagers, Mobile / Cellular Phones etc.
VSATs
Video Conferencing Equipment
Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signalling

K. Consumables including: -

C D.ROM / Compact Disk
Floppy Disk
Tapes DAT / DLT
Ribbons
Toners
Ink jet cartridges
Inks for out put devices

L. Others: -

Key Board
Monitor

Mouse
Multi Media Kits
Access Card
Electronics Purse
Electronics Wallet
Universal Pre Payment card
Smart card etc.

M. IT Enabled Services:-

Call Centres
Medical Transcriptions
Back Office Operations
Revenue Accounting and ancillary operations
Insurance Claim Processing
Web / Digital Content Development
Financial and Accounting processing
HR & Payroll processing
Bioinformatics
Animation & Design



Dy. Secretary to Government

Government of Rajasthan
Urban Development & Housing Department

No.F.10(53)UDD/3/06

Jaipur, Dated: 14.11.07

NOTIFICATION

1. With a view to facilitate the setting up of Information Technology Industries and IT enabled services in the State of Rajasthan, the State Government being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby provides that for Information Technology Units located in the Integrated Township Schemes established under policy declared on 29.3.2007, the Floor Area Ratio (FAR) shall be double of the permissible FAR for Commercial buildings as per prevailing building byelaws / regulation, subject to the condition that overall FAR of the Township scheme area shall not exceed 1 (one).

All other existing building regulations and provisions of Notification No. F.10(1)UD/3/2002 dated 29.3.2007 of Urban Development & Local Self Department would apply to the buildings used for Information Technology Units.

2. For areas not covered under the Integrated Township Schemes, maximum permissible FAR would be 2.00. Other building parameters shall be as prevailing in that use zone.

By Order of the
Governor,



(Sunil Kumar Sharma)

Dy. Secretary to Government

**RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT
AND INVESTMENT CORPORATION LIMITED,
UDYOG BHAWAN, TILAK MARG, JAIPUR-5**

No. IPP-6/25/95

Dated: 23/4/2007

OFFICE ORDER

Sub : Building Parameters for the IT Industries and ITeS.

The Board of Directors vide item (29) of the meeting held on 30th March, 2007 has accorded approval to newly framed Building parameters for IT Industries & ITeS as mentioned below:

Background:

These building regulations are based on Rajasthan Model Building Byelaws. All the local bodies in the Rajasthan including Jaipur Development Authority base their byelaws on this Model Building Byelaws. Rajasthan Model building Byelaws does not include any building regulations for the Industrial Building or IT buildings. As per provision of Model Building Byelaws RIICO Rules shall prevail in RIICO industrial areas:

RIICO Building Parameters for IT/ITeS plots:

Plot Area (In Sq mts.)	Maximum Ground Coverage (in %)	FAR	Minimum Set Back (in Mts.)				Maximum Height of the Building
700-1000	40	1.75	9.00	3.00	3.00	3.00	18 mts.
1000-1500	40	1.75	9.00	4.50	4.50	4.50	18 mts.
1500-2500	40	1.75	12.00	6.00	6.00	6.00	1.5 times the width of the front road subject to maximum 30 mts.
2500-4000	40	1.75	12.00	9.00	9.00	9.00	1.5 times the width of the front road subject to maximum 30 mts.
4000-10,000	40	2.00	15.00	9.00	9.00	9.00	1.5 times the width of the front road subject to maximum 30 mts.
10,000-20,000	40	2.50	20.00	9.00	9.00	9.00	1.5 times the width of the front road subject to maximum 60 mts.
20,000 and Above	40	2.50	25.00	9.00	9.00	9.00	1.5 times the width of the front road subject to maximum 60 mts.

Notes & Explanations:

- (a). Minimum plot size for IT/ITeS will be 1500 sq mts.
- (b). Parking requirements 1 ECS per 35 sq mts of FAR area
- (c). The permitted height of the building is subject to clearance form Civil Aviation Authority.
- (d). In plots measuring more than 40,000 sq mts., following incidental uses are permitted for benefits of units and their employees:
 - i). 4% of total FAR for Commercial facilities.
 - ii). 2% of total FAR for Recreational facilities.
 - iii). 10% of total FAR for residential facilities.
- (e). Permitted facilities like security room, L.T./H.T. meter room, time office, Chowkidar Quarters, Cycle/Scooter Parking etc are permitted in set backs area as per RIICO Disposal of Land Rules, 1979.
- (f). Other building control regulations for IT/ITeS plots may be followed as per Rajasthan Model Building bye-laws 2000 for commercial buildings and will be applicable to the existing IT/ITeS units also.
- (g). Obtaining of requisite fire safety related NOC from Municipal Body / concerned organization will also be necessary on the part of the plot holder.


Advisor (Infra)

Copy to:

1. FA/Advisor (Infra)/Advisor (A&M)
2. Secretary
3. GM (EIA) / GM (IT)/ GM (BP)
4. AGM (Finance)
5. Head of Technical/Project Cells:
 - (i) AGM (Civil)
 - (ii) AGM (Project-I)
 - (iii) AGM (Project-II)
6. All Unit Heads _ _ _ _ _
7. P&D Cell:
 - (i) Sr.DGM(RBY)
 - (ii) Sr. RM (DPJ)
 - (iii) Sr. RM (P&D)
 - (iv) RM (M&C)
8. DTP and Manager (Planning)
9. M&C Cell (IP&I)
10. Manager (P&D)
11. SO (P&D) / SI(P&D)/ Sr. Astd.(P&D)
NLF

Copy also to:
PS to MD: for kind information of M.D.


SRM
(P&D)

JPR5-417
JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
(COMMERCIAL) Vidyut Bhawan, Jan Path,
Jyoti Nagar, Jaipur - 302005

NO.JPD/CE(C)/XEN(C-I)/F.4(346)/Pt.II/D. 1823 Dt.
24.09.07

ORDER

Sub.-: Amendment in various provisions of different tariff schedule Under "Tariff for Supply of Electricity - 2004" & as amended form time to time.

In pursuance to order dt.31st August, 2007 of the Rajasthan Electricity Regulatory Commission, passed in the suo-moto petition for necessary rationalization in the existing tariff structure, the following amendments & also additions of new provisions are hereby issued. The Commission has also directed that these amendments/additions shall be applicable w.e.f. 1.10.2007 i.e. billing month of November, 2007.

In the said "Tariff for Supply of Electricity - 2004" in the "L.T. Tariff (Part - I) & "HT Tariff (Part-II) of the "Tariff Structure", following amendments are hereby issued:-

1. Following items are hereby added after Item - 22 under Sub-Clause -III "General Conditions of Application" of the Preamble :-

"(23) Power Purchase Cost Adjustment (PPCA) :

Formula :

PPCA for the consumption of energy by the consumers for nth quarter shall be worked-out as under:

$$\mathbf{PPCA_n : R_{n-1} - R_b}$$

(I-L)

Where:

PPCA_n = Power Purchase Cost Adjustment for nth quarter
:(Rs/kWh)

R_{n-1} = Weighted average net rate of power purchase cost from all
sources at Discom's periphery for (n-1)th quarter,
excluding UI, hydro & wind power generation (Rs/kWh).

R_b = Base weighted average net rate of power purchase cost
from all sources at Discom's periphery as determined by
the Commission from time to time, excluding UI, hydro &
wind power generation (Rs/kWh).

L = distribution loss in traction for different voltage category
of consumers, as under :

- i. 0% for EHV consumers i.e. 0.00
- ii. 3% for 33 KV consumers i.e. 0.03
- iii. 8% for 11KV consumers i.e. 0.08
- iv. 15% for LT consumers i.e. 0.15

NOTE:

- i. Net rate of power purchase shall be worked out after
accounting for the subsidy received from the State
Government towards extra energy purchase.
- ii. The rate of PPCA shall be worked out in Rs./unit rounded
off next second decimal place.
- III. It shall be levied on actual _ consumption/assessed
consumption of the consumers.
- iv. For this purpose, supply voltage at which the consumer is
actually connected, shall be considered.

Cost and Quantum of power purchase shall be based on bills/credits
received during the (n-1)th quarter irrespective of period to which it
pertains and shall include arrears or refunds, if any, for previous
period, not considered earlier.

(24) IT & ITES

IT Hardware and Software Industries. IT Software Industries
include IT Software, IT Services, IT Enabled Services, IT
Infrastructure and IT Training Institutions. The "IT Industry" shall
cover development, production and services related to IT Products.



2. "Minimum Billing" clause under tariff schedules Non-domestic Service (Schedule NDS/LT-2 & HT-2), Small Industrial Service (SP/LT-5), Medium Industrial Service (Schedule MP/LT6 & HT-3), Bulk Supply for Mixed Load (Schedule ML/LT-7 & HT-4) and Large Industrial Service (Schedule LP/HT-5), is hereby **DELETED.**

3. Due to abolition of "Minimum Billing", except agriculture category, the words "Minimum Billing Amount" shall be substituted by the words "Fixed Charges" wherever appearing in "Tariff Schedules", Regulations, Supply Code, "Terms & Conditions for Supply of Electricity" and all the orders relating to exemption/charging security & all such related instructions issued in the past.

4. Domestic Service (Schedule DS/LT-1)

The words "Community Kitchens under Mid Day Meal Programme" of the Govt. of Rajasthan & Goshalas" be added at the end of para - 2 of Clause - (a) "Applicability" under the tariff schedule "Domestic Service (Schedule DS/LT-1).

5. Add following new note at S.No.3(a) after existing note - 3 under tariff schedule Domestic Service (Schedule DS/LT-1) :-

"3(a) For Goshalas, the consumption shall be charged at half of Energy Charges & full Fixed Charges applicable for other consumers under this schedule."

6. The Note - 7 of the "Notes" under tariff schedule Domestic Service (Schedule DS/LT-1) shall be, substituted by the following, namely :-

If a connection under this schedule is provided at High Tension (11 KV or 33 KV) a rebate of 6% on the billed amount under this schedule will be given.

7. **Non-domestic Service (Schedule NDS/LT-2 & NDS/HT-2)**

Following words appearing in clause –(a) "Applicability" under the tariff schedules "Non-domestic Service (Schedule NDS/LT-2 and HT-2)" i.e.

"telephone exchanges other than belonging to BSNL, exclusive offices of BSNL not attached with their telephone exchanges" be substituted by the words;

"exclusive offices of Telephone/Mobile exchanges/switches not attached with their Telephone Exchanges/Switches,".

8. **Public Street Lighting (Schedule PSL/LT-3)**

Following words are added at the end of Clause - (a) "Applicability" under the tariff schedule "Public Street Lighting (Schedule PSL/LT-3)" :-

"Also available to "Street Lighting System" along the "National Highway" provided that there is separate metering for it."



9. **Small, Medium & Large Industrial Services (Schedule SP/LT-5), (MP/LT-6 & HT-3) and (LP/HT-5):**

Insert the following words between the words "Software Units" & "and Flour Mills" appearing in Clause - (a) "Applicability" under tariff schedules Small Industrial Service (Schedule SP/LT-5), Medium Industrial Service (Schedule MP/LT-6 & HT-3) and Large Industrial Service (Schedule LP/HT-5) :-

"IT & IT enabled Service"

10. **Bulk Supply for Mixed Load(Schedule ML/LT-7 and ML/HT-4):**

Following words appearing in Clause - (a) "Applicability" under tariff schedules "Bulk Supply for Mixed Load (ML/LT-7 & ML/HT-4) i.e. "Radio stations, TV stations and their transmitters, BSNL Exchanges/Switches including attached offices", be substituted by the words;

"Radio/TV Stations & their transmitters, all telephone exchanges/switches, BTS towers including attached offices"

11. **Power Factor Clause :**

Following paragraph is added just before last paragraph of Clause - (d) "Power Factor Clause" under tariff schedules "Domestic Service (Schedule DS/LT-1), "Non-domestic Service (Schedule NDS/LT-2 & NDS/HT-2), Medium Industrial Service

6/1


(Schedules MP/LT-6 & MP/HT-3), Bulk Supply for Mixed Load (Schedule ML/LT-7 & ML/HT-4), Residential Colony under "Domestic Service (Schedule DS/HT-1)" and Large Industrial Service (Schedule LP/HT-5):

However, where the installation of the meters at the consumer's premises comply with the requirements of the CEA (Installation & Operation of Meters) Regulations, 2006, the consumer shall maintain an average power factor of not less than 0.900 (90.0%). In case the average power factor falls below 0.900 (90.0%), a surcharge at 0.1% of energy charges for every 0.001 (0.1%) fall in average power factor below 0.900 (90.0%) shall be charged. Also an incentive of 0.1% of energy charges shall be provided if average power factor is above 0.950 (95.0%) for each 0.001 (0.1%) improvement above 0.950 (95.0%).

12. Following new clause is hereby added at the end of all the tariff schedules under LT & HT Tariff both :-

Rate worked out as per formula of "Power Purchase Cost Adjustment (PPCA) as per item - 23 under sub-clause – III "General Conditions of Application" of the preamble shall be leviable under this tariff schedule also.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'or' followed by a stylized signature.

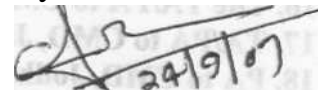
13. The voltage rebates appearing at the end of sub-item-1 under the heading "General" of Part-II "HT Tariff" is hereby substituted by the following, namely :-

"33 KV - 1.00%

132 KV - 3.00%"

Note : *Wherever the meters of required specifications are not provided, the existing incentive scheme, as above, shall continue till the required meters provided.*

By Order,



(B.L. Agarwal)
Chief Engineer (Comml.)

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director (Finance), Jaipur Discom, Jaipur (with 45 spare copies).
2. The Zonal/Dy.Chief Engineer (Zone/RP), Jaipur Discom,,Jaipur/Kota..
3. The Dy. Chief Engineer (MM), Jaipur Discom, Jaipur.
4. The Addl. Supdt. of Police (Vigl.), Jaipur Discom, Jaipur. (with 30 spare copies)
5. The Chief Personnel Officer, Jaipur Discom, Jaipur.
6. The Chief Accounts Officer, Jaipur Discom, .Jaipur.
7. The Dy. Chief Engineer/Supdtg. Engineer (power), RIICO, Jaipur.
8. The Supdtg. Engineer (), Jaipur Discom. _____.
9. The Secretary , Jaipur Discom, Jaipur.
- 10.The Sr. AO/AO/AAO (), Jaipur Discom, Jaipur.
- 11.The Executive Engineer (), Jaipur Discom, _____
- 12.The Executive Engineer (), Jaipur Discom, _____ ,alongwith 10 sparecopies for sending the same upto AENs/JENs/AROs/Accountants level under his jurisdiction.
13. The Executive Engineer (Elect.), J.D.A/R.H.B., Jaipur.
14. Executive Engineer (Griev.), Jaipur Discom, Jaipur.
15. The Company Secretary, Jaipur Discom/RRVPNL, Jaipur.
16. The TA/PA to CMD, RVPN, Jaipur, Discom, Jaipur
17. TA/PA to CMD, Jaipur Discom, Jaipur.
18. PA to CMD, Jodhpur/Ajmer Discom, Jodhpur/Ajmer.
19. P.S. to Hon'ble Energy Minister, Rajasthan, Jaipur.
20. P.S. to Secretary (Energy), Govt. of Rajasthan, Jaipur.
21. The Public Relations Officer, Jaipur Discom, Jaipur.
22. The Media Advisor, Jaipur Discom, Jaipur.
23. Sr. Accounts Officer (FP-5), A.G. Audit, Shed No.14/1, Jaipur.
24. Sr. Accounts Officer (CAW-III), A.G. Audit, Shed No.4/1, Jaipur.
25. The Asstt. Engineer (), Jaipur Discom, _____
26. The Zonal Commissioner, Ombudsman, Mini Secretariat, Near Collectorate, Jaipur.
27. _____



Government of Rajasthan
Department of Information Technology & Communication

No. F 5(207)/DoIT/Tech/04

Jaipur, Dated

NOTIFICATION

With a view to attract entrepreneurs for setting up Information Technology/Information Technology Enabled Services Units (IT/ITES Units) in the State and with a view to provide competitive base and remunerative hold to such units, the State Government being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby provides that all the fiscal incentives as given in the Rajasthan Investment Promotion Policy, as amended or announced from time to time, shall be available to the IT/ITES companies which set up IT units in the State, as specified in the Annexure appended to this notification, during the period starting from the date of announcement of the new IT & ITES Policy and upto 31st March 2012.

This issues with the approval of Finance Department vide UO note no. 12(9)FD/Tax/07 dated 05.06.2007.

By Order of the Governor,



(Aparna Arora)
Spl. Secretary to Government

ANNEXURE

CATEGORIES OF INDUSTRIES INCLUDED IN THE SCOPE OF INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY / UNITS

A. Computing devices including :-

Desktop
Personal Computer
Servers
Work-station
Nods
Terminals
Network PC
Home PC
Laptop Computers
Note book Computers
Palm top Computers/PDA

B. Network controller cards/Memories including :-

Network interface card (NIC)
Adaptor-ethernet / PCI / EISA / combo / PCMCIA
SIMMs-Memory
DIMMs-Memory
Central Processing Unit (CPU)
Controller-SCSI / Array
Processors-Processor / Processor Power Module / Upgrade

C. Storage Units including :-


Hard Disk Drives / Hard Drives
RAID Devices & their Controllers
Floppy Disk Drives
C.D. ROM Drives
Tape Drives – DLT Drives / DAT
Optical Disk Drives
Other Digital Storage Devices

D. Printers & Output Devices including :-

Dot-matrix
Laser jet
Ink jet
Desk jet
LED printers
Line printers
Plotters
Pass book Printers

E. Net working Products including: -

Hubs



Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

F. Software including: -

Application Software

Operating System

Middle Ware / Firm Ware

G. Power Supplies to Computer Systems including: -

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power Supplies

H. Net working / Cabling & related Accessories : -

(related to I.T.Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors,Terminal Blocks

Jack Panels,Patch Cord

Mounting Cord,Patch Panels

Back Boards,Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

I. Electronic Components: -

Printed circuit Board Assembly / populated PCB

Printed Circuit Board / PCB

Transistors

Integrated Circuits / Ics

Diodes / Thyristor / LED

Registers

Capacitors

Switches (On / Off, Push- button, Rocker etc.)

Plugs / Sockets / Relays

Magnetic Heads, Print Heads

Connectors

Microphones / Speakers

Fuses

J. Tele-communication Equipment including: -

Telephones

Videophones

Facsimile Machines / Fax cards

Tele-Printers / Telex machines

PABX / EPABX / RAX /MAX –Telephone exchange

Multi plexers / Muxes

Modems

Telephone Answering Machines
Tele-Communication Switching Apparatus
Antenna & Mast
Wireless Datacom Equipment
Receiving Equipments like pagers, Mobile / Cellular Phones etc.
VSATs
Video Conferencing Equipment
Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signalling

K. Consumables including: -

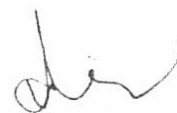
C D.ROM / Compact Disk
Floppy Disk
Tapes DAT / DLT
Ribbons
Toners
Ink jet cartridges
Inks for out put devices

L. Others: -

Key Board
Monitor
Mouse
Multi Media Kits
Access Card
Electronics Purse
Electronics Wallet
Universal Pre Payment card
Smart card etc.

M. IT Enabled Services:-

Call Centres
Medical Transcriptions
Back Office Operations
Revenue Accounting and ancillary operations
Insurance Claim Processing
Web / Digital Content Development
Financial and Accounting processing
HR & Payroll processing
Bioinformatics
Animation & Design



(Aparna Arora)
Spl. Secretary to Government

Government of Rajasthan
Department of Information Technology & Communication

No. F 5(207)/DoIT/Tech/04

Jaipur, Dated

NOTIFICATION

With a view to encourage establishment of Small And Medium Enterprises (SMEs) in the Information Technology / Information Technology Enabled Services (IT/ITES) sector, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby provides for one time subsidy upto Rs. 25/- lacs at the rate of Rs. 10,000/- per employee, to the first five such IT/ITES Companies / units making investment in the State and directly employing more than fifty employees in the case of IT Industry or one hundred employees in the case of ITES Industry, in accordance with the guidelines formulated by the Information Technology and the Communication Department.

This notification shall be applicable to those said new IT/ITES Companies/units which are established after the announcement of the new IT/ITES Policy and up to the period ending on 31st March, 2012.

Explanation 1. IT/ITES industries are defined as under:-

- (i). **“IT industries”** include IT Hardware & Software Industries. IT Software Industries include IT Software, IT Services, IT Enabled Services, IT Infrastructure and IT Training Institutions. The “IT Industry” shall cover development, production and services related to IT Products. Here IT includes IT & Telecommunications.
- (ii). **“IT Software”** is defined as any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated for providing interconnectivity to a user, by means of an automatic data processing machine falling under heading “IT Products”, but does not include “non-IT products”.
- (iii). **“IT Products”** are defined as computer, digital-data communication and digital-data broadcasting products as notified by the Ministry of Finance, Government of India or Central Board of Excise & Customs.
- (iv). **“IT Service”** is defined as any service which results from the use of any IT software over a system of IT products for realizing value addition.
- (v). **“IT Enabled Service”** is defined as any product or service that is provided or delivered using the resources of Information and Communication Technology.
- (vi). **“IT Training Institution”** means an institution imparting training in the field of IT, IT Enabled Service and IT Services and having an accreditation / affiliation from DOEACC (GOI) or any University established by Law in India or any Institution which has a Deemed University status as per the UGC Act.
- (vii). **“IT Infrastructure”** means the physical infrastructure built by a firm or a builder and sold / leased or transferred on lease-cum-sale to an IT industry for its use or the infrastructure built by an IT industry for its own use.
- (viii). **“Telecommunications”** means telecommunications companies including Basic Telecom Service Providers, VSAT, Cellular (Mobile) companies, Telecom Infrastructure Companies, LAN, ISPs and any other value added services licensed by Ministry of Communications & IT, Government of India.



Explanation 2. Small and Medium Scale IT / ITES Enterprises are defined as follows:

IT INDUSTRY:

- (i). **Small Enterprises:** IT Industry units/companies with investment in Plant & Machinery to the tune of above Rs.25 lacs and up to Rs.5 crores are classified as Small Enterprises.
- (ii). **Medium Enterprises:** IT Industry units/companies with investment in Plant & Machinery to the tune of above Rs.5 Crores and up to Rs. 10 Crores are classified as Medium Enterprises.

ITES INDUSTRY:

- (i). **Small Enterprises:** ITES units/companies with investment in Equipment up to Rs.10 lacs are classified as Micro Enterprises. ITES units/companies with investment in Equipment to the tune of above Rs.10 lacs and up to Rs.2 crores are classified as Small Enterprises.
- (ii). **Medium Enterprises:** ITES units/companies with investment in Plant & Machinery to the tune of above Rs.2 Crores and up to Rs. 5 Crores are classified as Medium Enterprises.

This issues with the approval of Finance Department vide ID no. 59/EAD/07 dated 23.08.2007.

By Order of the Governor,



(Aparna Arora)

Spl. Secretary to Government

Government of Rajasthan
Department of Information Technology & Communication

No. F 5(207)/DoIT/Tech/04


Jaipur, Dated

NOTIFICATION

With a view to provide a special package of incentives to the Information Technology/Information Technology Enabled Services (IT/ITES) Mega Projects, the State Government being to the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby provides that such IT/ITES mega projects shall be allowed a special package of incentives of Rs. 10,000/- per employee on one time basis and in accordance with the guidelines formulated by the Information Technology & Communication Department..

Explanation I. IT Industries are defined as under:-

- (i). **“IT industries”** include IT Hardware & Software Industries. IT Software Industries include IT Software, IT Services, IT Enabled Services, IT Infrastructure and IT Training Institutions. The “IT Industry” shall cover development, production and services related to IT Products. Here IT includes IT & Telecommunications.
- (ii). **“IT Software”** is defined as any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated for providing interconnectivity to a user, by means of an automatic data processing machine falling under heading “IT Products”, but does not include “non-IT products”.
- (iii). **“IT Products”** are defined as computer, digital-data communication and digital-data broadcasting products as notified by the Ministry of Finance, Government of India or Central Board of Excise & Customs.
- (iv). **“IT Service”** is defined as any service which results from the use of any IT software over a system of IT products for realizing value addition.
- (v). **“IT Enabled Service”** is defined as any product or service that is provided or delivered using the resources of Information and Communication Technology.
- (vi). **“IT Training Institution”** means an institution imparting training in the field of IT, IT Enabled Service and IT Services and having an accreditation / affiliation from DOEACC (GOI) or any University established by Law in India or any Institution which has a Deemed University status as per the UGC Act.
- (vii). **“IT Infrastructure”** means the physical infrastructure built by a firm or a builder and sold / leased or transferred on lease-cum-sale to an IT industry for its use or the infrastructure built by an IT industry for its own use.
- (viii). **“Telecommunications”** means telecommunications companies including Basic Telecom Service Providers, VSAT, Cellular (Mobile) companies, Telecom Infrastructure Companies, LAN, ISPs and any other value added services licensed by Ministry of Communications & IT, Government of India.

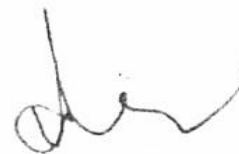


Explanation II. IT/ITES Mega Projects shall be those projects that create employment of more than **500 people in the case of IT industry or 1000 people in ITES Industry.**

Explanation III. The said Mega IT/ITES Projects shall be required to be set up after the announcement of the new IT & ITES Policy and upto 31st March 2012.

This issues with the approval of Finance Department vide ID no. 54/EAD/07 dated 13.07.2007.

By Order of the Governor,



(Aparna Arora)

Spl. Secretary to Government

Government of Rajasthan
Urban Development & Housing Department

No.F.10(53)UDD/3/06

Jaipur, Dated : 14.11.07

NOTIFICATION

With a view to encourage establishment of Micro, Small And Medium Enterprises (SMEs) in the Information Technology / Information Technology Enabled Services (IT/ITES) sector, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby provides for rebate on rate as follows:

	Amount of Investment	Allotment rate (% of reserve price)
1.	<u>For IT Industry</u>	
	i. Micro Enterprise (investment upto Rs. 25 Lakhs)	70%
	ii. Small Enterprise (above Rs.25 lacs and up to Rs.5 crores)	60%
	iii. Medium Enterprise (above Rs.5 Crores and up to Rs.10 crores)	50%

2.	<u>For ITES Industry</u>	
	i. Micro Enterprise (investment upto Rs. 10 Lakhs)	70%
	ii. Small Enterprise (above Rs.10 lacs and up to Rs.2 crores)	60%
	iii. Medium Enterprise (above Rs.2 Crores and up to Rs.5 crores)	50%

This notification shall be applicable to those said new IT/ITES Companies/units which are established after the announcement of the new IT/ITES Policy and up to the period ending on 31st March, 2012.

Explanation 1.

Land shall be allotted, subject to availability in the desired location.

Explanation 2:

The allotted land shall exclusively be used for the purpose for which it stands allotted; else it shall be acquired by the Government, without any compensation besides black listing the individual / society / Trust / Firm and imposing a penalty.

Explanation 3: IT/ITES industries are defined as under:-

- (ix). **“IT industries”** include IT Hardware & Software Industries. IT Software Industries include IT Software, IT Services, IT Enabled Services, IT Infrastructure and IT Training Institutions. The “IT Industry” shall cover development, production and services related to IT Products. Here IT includes IT & Telecommunications.
- (x). **“IT Software”** is defined as any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated for providing interconnectivity to a user, by means of an automatic data processing machine falling under heading “IT Products”, but does not include “non-IT products”.
- (xi). **“IT Products”** are defined as computer, digital-data communication and digital-data broadcasting products as notified by the Ministry of Finance, Government of India or Central Board of Excise & Customs.
- (xii). **“IT Service”** is defined as any service which results from the use of any IT software over a system of IT products for realizing value addition.
- (xiii). **“IT Enabled Service”** is defined as any product or service that is provided or delivered using the resources of Information and Communication Technology.

- (xiv). **“IT Training Institution”** means an institution imparting training in the field of IT, IT Enabled Service and IT Services and having an accreditation / affiliation from DOEACC (GOI) or any University established by Law in India or any Institution which has a Deemed University status as per the UGC Act.
- (xv). **“IT Infrastructure”** means the physical infrastructure built by a firm or a builder and sold / leased or transferred on lease-cum-sale to an IT industry for its use or the infrastructure built by an IT industry for its own use.
- (xvi). **“Telecommunications”** means telecommunications companies including Basic Telecom Service Providers, VSAT, Cellular (Mobile) companies, Telecom Infrastructure Companies, LAN, ISPs and any other value added services licensed by Ministry of Communications & IT, Government of India.

By Order of the Governor



(Sunil Kumar Sharma)
Dy. Secretary to Government

Government of Rajasthan
Department of Information Technology & Communication

No. F 5(207)/DoIT/Tech/04

Jaipur, Dated

NOTIFICATION

With a view to provide a special package of incentives to the Information Technology / Information Technology Enabled Services (IT/ITES) training institutes, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby provides that an incentive of Rs. 2,000/- per candidate will be provided to training centers whose candidates find placement in IT & ITES companies after successful training on communication/soft skills. This set of incentives would be provided only to those training institutions which:

- (i). are able to place a minimum of **200** candidates per annum for training institutes located in Jaipur.
- (ii). are able to place a minimum of **100** candidates per annum for training institutes located elsewhere in Rajasthan.
- (iii). are registered online with the Department of Higher Education, Government of Rajasthan, as per the norms and criteria laid down by the State Government.
- (iv). maintain online details about registered training centers, information of candidates trained and information of candidates placed on the website notified by the State Government.

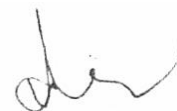
This notification shall be applicable all IT/ITES training institutes and shall be valid up to the period ending on 31st March, 2012.

Explanation 1:

The incentive shall be provided on submission of proof of such placements obtained from the IT / ITES companies providing employment opportunities to the candidates.

Explanation 2: IT/ITES industries are defined as under:-


- (i). **“IT industries”** include IT Hardware & Software Industries. IT Software Industries include IT Software, IT Services, IT Enabled Services, IT Infrastructure and IT Training Institutions. The “IT Industry” shall cover development, production and services related to IT Products. Here IT includes IT & Telecommunications.
- (ii). **“IT Software”** is defined as any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated for providing interconnectivity to a user, by means of an automatic data processing machine falling under heading “IT Products”, but does not include “non-IT products”.
- (iii). **“IT Products”** are defined as computer, digital-data communication and digital-data broadcasting products as notified by the Ministry of Finance, Government of India or Central Board of Excise & Customs.
- (iv). **“IT Service”** is defined as any service which results from the use of any IT software over a system of IT products for realizing value addition.
- (v). **“IT Enabled Service”** is defined as any product or service that is provided or delivered using the resources of Information and Communication Technology.



- (vi). **“IT Training Institution”** means an institution imparting training in the field of IT, IT Enabled Service and IT Services and having an accreditation / affiliation from DOEACC (GOI) or any University established by Law in India or any Institution which has a Deemed University status as per the UGC Act.
- (vii). **“IT Infrastructure”** means the physical infrastructure built by a firm or a builder and sold / leased or transferred on lease-cum-sale to an IT industry for its use or the infrastructure built by an IT industry for its own use.
- (viii). **“Telecommunications”** means telecommunications companies including Basic Telecom Service Providers, VSAT, Cellular (Mobile) companies, Telecom Infrastructure Companies, LAN, ISPs and any other value added services licensed by Ministry of Communications & IT, Government of India.

This issues with the approval of Finance Department vide UO note no. F 8(53)Part-II/FD/EAD/07 dated 27.04.2007.

By Order of the Governor,



(Aparna Arora)
Spl. Secretary to Government

Government of Rajasthan
Department of Information Technology & Communication

No. F 5(207)/DoIT/Tech/04

Jaipur, Dated

NOTIFICATION

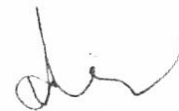
With a view to give impetus to innovations in the IT/ITES sector, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby provides for remittance up to a limit of Rs. 50,000/- by way of reimbursement of the ICT patent cost after the announcement of the new IT & ITES Policy by the State Government and up to 31st March, 2012 only to Government institutions / individuals / firms (without profit) and non-profit organizations. The reimbursement shall be made only after the grant of patent to the innovator.

Explanation 1: IT/ITES industries are defined as under:-

- (i). **“IT industries”** include IT Hardware & Software Industries. IT Software Industries include IT Software, IT Services, IT Enabled Services, IT Infrastructure and IT Training Institutions. The “IT Industry” shall cover development, production and services related to IT Products. Here IT includes IT & Telecommunications.
- (ii). **“IT Software”** is defined as any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated for providing interconnectivity to a user, by means of an automatic data processing machine falling under heading “IT Products”, but does not include “non-IT products”.
- (iii). **“IT Products”** are defined as computer, digital-data communication and digital-data broadcasting products as notified by the Ministry of Finance, Government of India or Central Board of Excise & Customs.
- (iv). **“IT Service”** is defined as any service which results from the use of any IT software over a system of IT products for realizing value addition.
- (v). **“IT Enabled Service”** is defined as any product or service that is provided or delivered using the resources of Information and Communication Technology.
- (vi). **“IT Training Institution”** means an institution imparting training in the field of IT, IT Enabled Service and IT Services and having an accreditation / affiliation from DOEACC (GOI) or any University established by Law in India or any Institution which has a Deemed University status as per the UGC Act.
- (vii). **“IT Infrastructure”** means the physical infrastructure built by a firm or a builder and sold / leased or transferred on lease-cum-sale to an IT industry for its use or the infrastructure built by an IT industry for its own use.
- (viii). **“Telecommunications”** means telecommunications companies including Basic Telecom Service Providers, VSAT, Cellular (Mobile) companies, Telecom Infrastructure Companies, LAN, ISPs and any other value added services licensed by Ministry of Communications & IT, Government of India.

This issues with the approval of Finance Department vide ID no. 70/FD/EAD/07 dated 14.09.2007.

By Order of the Governor,



(Aparna Arora)

Spl. Secretary to Government

**GOVERNMENT OF
RAJASTHAN REVENUE (Gr. 6)
DEPARTMENT**

No. F.9(234)Rev.VI/2007/57
2007

Jaipur, dated: 27-11-

NOTIFICATION

In exercise of the Powers conferred by section 100 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Industrial Areas Allotment) Rules, 1959, namely:-

1. Short title and Commencement.- (!) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Industrial Areas Allotment) (Amendment) Rules, 2007.

(ii) They shall come into force at once.

2. Substitution of rule I-A and I-AA.-The existing rule 1-A, 1-AA of the Rajasthan Land Revenue (Industrial Areas Allotment) rules, 1959 hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

" **1 A Definition.-** in these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context;

(i) '**District Level Committee**' means the committee constituted

by the State Government for a district from time to time under

clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules,

2004;

(ii) '**Industrial Area**' means an area of land which may have been reserved and set apart or may hereafter be reserved or set apart under section 92 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, for the

purpose of setting up an industry or industries including essential welfare and supporting services e.g. post office, labour colony, residential colony/ housing complex and township, educational institution, R.S.E.B. power station and water and sewerage facilities, dispensary or hospital , police fire service station, bank, weigh-bridge, shops and markets, cinema, hotel and restaurant and petrol pump;

(iii) 'IT Industry' means IT Hardware, Software Industry, IT Services, IT Enabled Services, IT Infrastructure and IT Training Institutions. It shall cover development, production and services related to IT Products and includes IT and Telecommunications;

(iv) 'IT Enabled Service' means any product or service that is provided or delivered using the resources of Information and Communication Technology;

(v) 'IT' means information technology;

(vi) 'Peripheral Belt' means the peripheral belt as indicated in the Master Plan or Master Development Plan of a city or a town prepared under any law for time being in force and where there is no Master Plan or Master Development Plan or where peripheral belt is not indicated in such plan, the area as may be notified by the State Government in the Urban Development and Housing Department from time to time and where any part of a village falls within the peripheral belt, the whole village shall be deemed to be within the peripheral belt;

(vii) 'Rural Area' means an area which is not included in the notified area of urban bodies and their urbanisable limits or periphery belt;

(viii) 'Tourism unit' means tourism project of the following categories approved by the Tourism department, Government of Rajasthan.

(a) a heritage hotel;

(b) any other hotel with accommodation of 25 rooms and more;

(c) a camping site with furnished tented accommodation, having at least fifty tents along with bathroom and toilet facilities;

(d) a holiday resort providing sports and recreational facilities, riding, swimming and social amenities with boarding & lodging arrangements in Cottages; and

(e) an amusement park providing various type of rides, games and amusement for children as well as for adults.

(ix) 'Urban Bodies' means bodies constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 or the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) or the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982)."

3.Amendment of rule 2.- After the existing clause (b) to the rule 2 of the said rules, following new clause (bb) shall be inserted, namely:-

"(b b)- for the setting up of IT Industries, Government land shall be allotted by the State Government in the Revenue Department on the recommendation of the Department of Information Technology and Communication."

4.Amendment of rule 3A.- After the existing rule 3A of the said rules following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that for the allotment of Government agricultural land for setting up of IT Industries in rural areas, the price of the land shall be charged from the allottee at the rate of 75% of market rate determined by the District level committee of the same class of

agricultural land subject to the condition that the IT Industry should be established before 31 March 2012."

By order of the Government


(K.G. Agarwal)
Deputy Secretary to Govt.

Copy forwarded to :-

1. P.S. to Hon'ble Chief Minister.
2. S.A. to Hon'ble Revenue Minister.
3. D.S. to Chief Secretary.
4. P.S. to Principal Secretary, Revenue/Information Technology.
5. P.S. to Revenue Secretary.
6. All Divisional Commissioner, Rajasthan.
7. All Collectors, Rajasthan.
8. Registrar, Board of Revenue, Ajmer.
9. Director, Public Relation, Jaipur.
10. Superintendent, Rajasthan Central Govt. Press, Jaipur for publication of the Notification in the Rajasthan Official Gazette extraordinary dated 27-11-2007.
11. 'RAVIRA', Board of Revenue, Ajmer.
12. Joint Registrar, (Library) Judges, Supreme Court, New Delhi.
13. Dy. Registrar (Accounts & Finance), B.O.R., Ajmer.
14. All Deputy Secretaries, Revenue Department.
15. D.L.R., Col./ Group-7/ Group-6.
16. Guard file.


(K.G. Agarwal)
Deputy Secretary to Govt.